

10-11-25

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 2 से 8 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी वकील द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल रहे।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

प्रार्थी वकील की बहस है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 237/127 रकबा 1.6349 हैक्टेयर भूमि ग्राम देवलियाली तहसील समदडी में अवस्थित है। प्रार्थी विवादित भूमि का रेकॉर्ड खातेदार है। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थी की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से विप्रार्थीगण माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते हैं, प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहता है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि का नेखमबंदी किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

विप्रार्थी अधिवक्ता का कथन किया कि रा.भू.अ. की धारा 111-128 के अनुसार नेखमबंदी करवाने से पूर्व प्रार्थी को विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाना आवश्यक है, पटवारी हल्का की सीमाज्ञान रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने सीमाज्ञान करवाने से इन्कार किया गया है, प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 2 से 8 अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्त है विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के कब्जा काश्त भूखण्ड पर जोर जबरन अतिक्रमण करने या तारबंदी नष्ट करने की कार्यवाही नहीं की गई है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर आधारित होने से एवं विवादित भूमि का सीमाज्ञान के अभाव होने से काबिल-ए-खारिज है।

हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी, और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकॉर्ड, दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट को गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का विवेचन किया जिसमें पाया कि ग्राम देवलियाली के खसरा संख्या 237/127 रकबा 1.6349 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है इस प्रकार प्रार्थी निवादित भूमि के रिकॉर्ड खातेदार है और रिकॉर्ड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है जिसका प्रार्थी हकदार प्रतीत होता है हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. का उल्लेख करना उचित समझते हैं जिसके अनुसार :- धारा 128:- सीमा सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेंगे :-

1[परन्तु खेतों की सीमाओं सम्बन्धी आवेदन पत्र, जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐस विवाद उठाने की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेंगे तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेंगे]

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)




अनवान नौनामिरे v/s TPR रसपणी

मुकदमा नंबर 281 / 2025

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर पर किया जाना है पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 02.04.2025 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं को लेकर कोई विवाद उल्लेख नहीं है ऐसी स्थिति में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 128 (1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि सरहद मौजा देवलियाली तहसील समदडी के खसरा संख्या 237/127 रकबा 1.6349 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश हेतु विधिनुसार कार्यवाही हेतु तहसीलदार समदडी को निर्देशित किया जाता है विवाद की स्थिति होने पर पालना पेश करे।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दपतर हो।


उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)